भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या466

दिनांक06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु पंद्रहवां वित्त आयोग

†466. श्री जयदेव गल्लाः

क्या **पंचायती राज**मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण निकायों/पंचायतों द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित की गई निधियों के वित्तीय कुप्रबंधन के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे आरोपों का पता लगाने के लिए कोई सवींक्षा/लेखापरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि में से वर्ष 2023-24 के लिए आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने निधियों के उपयोग के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) जी हां, महोदय; आंध्र प्रदेश की पांच निरुद्देश्यता से चुनी गई पंचायतों वरगानी, एडुपुगल्लू, पेडयादरा, बुट्टायागुडेम (पेसा ग्राम पंचायत) और भोगापुरम में जांच की गई।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि के आवंटन, जारी और व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका :

चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत आवंटित धनराशि, जारी और व्यय का विवरण (रूपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	पंद्रहवा वित्त आयोगके तहत जारी धनराशि	खर्च		
			सीएफएमएस *	ई-ग्रामस्वराज	कुल
2020-21	2625	2625	1950.80	0	1950.80
2021-22	1939	1917.85	1871.58	0	1871.58
2022-23	2010	1976.75	362.06	686.4	1048.46
2023-24	2031	399.45	0	0	0
Total	**8605**	**6919.05**	**4184.44**	**686.4**	**4870.83**

* सीएफएमएस- विस्तृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(घ) पंदरहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों को रु. 399.45 करोड़ जारी किए गए हैं।

(ङ) जी नहीं, महोदय।

*****